मंत्री कृष्णपाल के घर पर छात्रों का प्रदर्शन

अब बच्चे ही सुधारेंगे नारियल फ़ोड़ नेताओं को

फ़रीदाबाद (म.मो.) आये दिन नारियल फ़ोड़ने व झूठे बयान देकर जनता को बहकाने वाले स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के सेक्टर 28 स्थित घर के बाहर सैंकड़ों स्कूली छात्र-छात्राओं ने ज़ोरदार प्रदर्शन करते हुए घंटों तक धरना दिया। हाथों में नारे लिखी तख्तीयां लिये व जोर-जोर से नारे लगाते ये बच्चे मन्त्री के पड़ोस में चल रहे एक सरकारी स्कूल के थे। पहली से बारहवीं तक का यह स्कूल कहने को तो 'मॉडल' स्कूल का दर्जा प्राप्त है लेकिन यहां तमाम कक्षाओं में पढ़ने वाले कुल 800 छात्र-छात्राओं के लिये मात्र 5 अध्यापक हैं। शुकर यह है कि अभी इस स्कूल में 12 वीं कक्षा नहीं आई है, केवल 11 वीं कक्षा तक इसी साल पहुंचा है।

इसके अलावा स्कूल में न तो पीने लायक पानी है न ढंग के शौचालय। बैठने का बैंच नहीं हैं तो नंगे फ़र्श पर ही बैठ कर समय पूरा कर दिया जाता है। कम्प्यूटर लैब तो है परन्तु उसमें कम्प्यूटर नहीं हैं। बिजली कभी रहती नहीं है, इसलिये जो 2-4 पंखे लगे भी हैं वे चल नहीं पाते।

संदर्भवश इस मॉडल स्कूल का इतिहास भी पाठक जान लें। करीब 18-20 वर्ष पूर्व 'हूडा' विभाग ने स्कूल के नाम की एक आलीशान इमारत बनाई थी। यह इमारत शहर के किसी भी निजी स्कूल से बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं थी। बनने के बाद, जैसी कि इस देश में प्रथा है, करीब 15-16 साल तक यहां इमारत विरान पड़ी रही। असामाजिक तत्वों ने इसमें कब्ज़े करने शुरू कर दिये, असामाजिक धंधे इसमें चलने लगे। सकूल के लम्बे चौड़े खेल मैदान में से आधे को सांसद कृष्णपाल ने अपने घर के निकटस्थ पार्क में जुड़वा लिया।

करीब 3 वर्ष पूर्व रितु चौधरी नामक एक बीईओ (खंड शिक्षा अधिकारी) यहां तैनात होकर आई। उन्होंने यह सारी कहानी तत्कालीन शिक्षा आयुक्त सुरीना राजन को बताई, उन्होंने मौका मुआयना करने के पश्चात तमाम विभागीय एवं 'हूडा' की औपचारिकतायें पूरी करा कर इमारत को कब्ज़े में लिया। लेकिन सेक्टरों की उच्च स्तरीय जेंट्री को देखते हुए इसे मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय लिया जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया। नौवीं से बारहवीं तक के इस स्कूल में कम्प्यूटरों से सुसज्जित लैब तथा संगीत शिक्षा के लिये अनेकों वाद्ध यन्त्र रखे गये। इस के लिये चुन-चुन कर बेहतरीन एवं पर्याप्त स्टाफ़ रखा गया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए यहां दाखला लेने वालों की भीड़ लग गयी। बाकायदा टैस्ट लेकर दाखला दिया जाता था।

वक्त बदला, सरकार बदली। सुरीना राजन हरियाणा से प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र (दिल्ली) में चली गयी। कृष्णपाल की चापलूसी न करने पर बीईओ रितु चौधरी का तबादला करा दिया गया। उनकी जगह मनीश चौधरी आ गयी। उन्होंने इस स्कूल में अपने जैसे निकम्मे व चापलूस स्टाफ़ को भरना शुरू कर दिया। गत डेढ वर्ष में शायद ही कोई ऐसा महीना गया होगा जिसमें किसी न किसी बहाने कृष्णपाल या उनका पुत्र देवेन्द्र यहां नारियल फ़ोड़ने न आये हों। कभी पौधारोपण तो कभी कोई जलसा तो कभी कुछ। जाहिर है इन सब व्यर्थ के कामों से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही थी। इसके अलावा जो बढ़िया एवं मेहनती अध्यापक यहां तैनात हैं वे न तो बीईओ की जी हुजूरी करते हैं और उनके चापलूस अध्यापक सतीश चौधरी की तो करनी ही क्या थी। लिहाज़ा बच्चों के इस प्रदर्शन के पीछे उन 3 बढ़िया शिक्षकों को बलि का बकरा बनाने की तैयारी है।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार का सकूली शिक्षा विभाग, 'हूडा विभाग' पंचायत विभाग व अन्य विभाग जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके मुताबिक प्रत्येक बच्चे पर 4000 रुपया मासिक से अधिक खर्च हो रहा है, न आवश्यक साजोसामान, न ढंग की इमारत, न कोई आवश्यक सुविधा। तो यह इतनी बड़ी रकम आखिर जा कहां रही है? जबकि इससे कम फ़ीस लेने वाले निजी स्कूल तमाम तरह की सुविधाओं व बेहतरीन शिक्षक उपलब्ध करा रहे हैं। जाहिर है शासक वर्ग में बैठे लोग चाहे वे कांग्रेसी हों या चौटालावादी या आज के भाजपाई, सभी का एकमात्र लक्ष्य जनता के धन की लूट तथा शिक्षा का सत्यानाश करना है।

कुछ भी हो छात्रों के इस साहसिक प्रदर्शन ने समाज को एक नया रास्ता दिखाया है जो कि सराहनीय एवं अनुकरणीय है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण दायित्व के साथ खिलवाड़ कर रही इस सरकार से निपटने के लिये तमाम स्कूली बच्चों को ही संगठित होकर सड़कों पर उतरना होगा, तभी ये जुमलेबाज नारियल फ़ोड़ नेता काबू आ पायेंगे।

29 हज़ार करोड़ का कोयला खरीद घोटाला

''भ्रष्टाचार मुक्त भारत'' के नाम से सत्ता में आये देश के नये रहनुमा भी भ्रष्टाचार के जहरीले पेड़ को बढ़ने से रोकने में असफल रहे। वायदे सिर्फ़ हवा में लटके रह गये। वित्त मंत्रालय के तहत काम करनेवाली डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलीजेन्स (डीआरआई) ने आयातित कोयला कीमतों में अवैध बढ़ोत्तरी से किये गये 29 हज़ार करोड़ के घोटाले का पर्दाफ़ाश किया था। डीआरआई पर भी आरोप था कि उसने घोटाले की रकम को बहुत कम करके बताया था। घोटाले में सत्ताधारी पार्टी की चहेती कम्पनियों के फ़से होने के चलते मुख्यधारा के मीडिया ने इस पर चुप्पी साधे रखी। इस घोटाले में अडाणी ग्रुप की 5 कम्पनियां, अनिल अम्बानी की 2, रुइया परिवार के एस्सार ग्रुप की 2 सज्जन जिन्दल की एक तथा एम वैंकटरमैया और एस प्रभाकर राव के एनएसएल ग्रुप की 5 कम्पनियों समेत चालीस से ज़्यादा कम्पनियां लिप्त पायी गयी हैं। इस मामले में सीबीआई, बैंक ऑफ़ बडौदा के दो अधिकारियों एस के गर्ग और जयनेश दूबे को पिछले साल गिरफ़्तार भी कर चुकी है।

यह घोटाला इन भारतीय कम्पनियों और दलालों के तौर पर काम करने वाली मध्यस्थ कम्पनियों के बीच आपसी सांठ-गांठ से सम्पन्न हुआ। निजी कम्पनियों का घोटाले में शामिल होना कोई नयी बात नहीं है। 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला और राडिया टेप खुलासा निजी कम्पनियों की कारस्तानी थी। सरकारें उनसे मिलीभगत करके उन्हें बचा लेती हैं और उम्मीद है कि नये घोटालेबाज़ों को भी बचा लिया जायेगा।

भारत में कोयले का सबसे अधिक इस्तेमाल बिजली निर्माण के लिए पॉवर प्लान्टों में ईंधन के रूप में होता है कोयला विदेशों से मंगाया जाता है जबकि हमारे यहां कोयले की खानों की कमी नहीं है, लेकिन निजी कम्पनियों का कहना है कि हमारे यहां के कोयले की जलने की क्षमता कम है, उससे कम ऊर्जा ही निकल पाती है। इसीलिये वे आसानी से सरकार पर दबाव बनाते हैं कि कोयले की आपूर्ति दूसरे देशों से पूरी की जाये। विशेषज्ञों का मानना है कि दूसरे देशों के कोयले और भारत के कोयले की गुणवत्ता में ज़्यादा अन्तर नहीं है, जबकि दोनों के मूल्यों में भारी अन्तर है। दरअसल बाहर का कोयला निजी कम्पनियों को कमाई के ऊपर मिलने वाली मलाई है।

भरतीय निजी और सार्वजनिक कम्पनियों के पॉवर प्लान्टों के लिए इंडोनेशिया की कम्पनियों से कोयला आता है। भारतीय कम्पनियां सीधे तौर से इंडोनेशिया से कोयला न खरीदकर दूसरी मध्यस्त कम्पनियों के द्वारा कोयला खरीदती हैं। मध्यस्त कम्पनियां इंडोनेशिया की कम्पनियां से सस्ती दर पर कोयला खरीद लेती हैं और उसे ऊंचे दाम पर भारतीय कम्पनियों को बेच देती हैं। भुगतान के इसी अन्तर से दोनों तरह की कम्पनियां मुनाफ़ा कमाती हैं। हमारी सरकार इन कम्पनियों को सब्सिडी के नाम पर भारी छूट भी देती है। इस तरह इनके मुनाफ़े का दूसरा रास्ता भी खुल गया है जो जनता की जेब से होते हुए सीधे पूंजीपतियों की तिजोरी में जाता है।

डीआरआई ने महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में 80 से अधिक शिपिंग कम्पनियों पर कोयले के वास्तविक मूल्य की जांच-पड़ताल करने के लिए निरीक्षण शुरू किया था। वहां उन्होंने कोयले की कैलोरी क्षमता की जांच-पड़ताल की, जिसमें उसके गुण और वास्तविक मूल्य का पता लगाया जा सके। जब्त किये गये दस्तावेज़ों से आयातित कोयले के वास्तविक मूल्य के बारे में मिली जानकारी जांच कमेटी को परेशान कर देने वाली थी। तमाम कम्पनियों के दस्तावेज़ों से पता चलता है कि कम्पनियों द्वारा कोयले का वास्तविक मूल्य के दोगुने से भी अधिक दिखाया गया है। इसके कारण केवल तीन साल के अन्दर वर्ष 2011-2014 तक 29,000 करोड़ रुपये का घोटाला किया गया। जांच के बाद डीआरआई का कहना है कि अगर भारतीय कम्पनियां कोयले का वास्तविक मूल्य दर्शाती तो एक यूनिट बिजली का खर्च 1 रुपये से भी कम आता। जांच एजेंसी ने केवल 3 साल का आंकड़ा जुटाया है जिसके आधार पर बिजली बनाने वाली निजी कम्पनियों ने इंडोनेशिया से खरीदे गये मूल्य को अधिक दिखाकर 29,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की। मौजूदा सरकार इन घोटालेबाज कम्पनियों को ही भारत भाग्य विधाता मानकर टैक्स में छूट दे रही है, सस्ती दर पर ज़मीन मुहैया कर रही है। काग़जी तौर पर घाटा दिखाने पर उन्हें उबारने तक में मदद करती है। कम्पनियों के प्रोत्साहन के नाम पर उन्हें भारी-भरकम राहत पैकेज दिये जा रहे हैं और समय-समय पर कर्ज़ भी माफ़ कर दिये जाते हैं। दूसरी तरफ़ हमारे किसान साहूकारों, धन्नासेठों के भारी कर्ज के चलते आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, फ़िर भी उन्हें कोई राहत पैकेज देना तो दूर की बात, उनकी मेहनत की फ़सल का वाजिब दाम भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। आखिर देश क्या केवल पूंजीपतियों का है? केन्द्र सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली कई जांच एजेंसियों पर रोक लगा दी जिससे वे भ्रष्टाचार को पकड़ ही न सकें। यह तो कुछ इस तरह ही हुआ जैसे गरीबी को खत्म करना है तो गरीबी के बारे में बात करना बंद कर दो। यानी मुन्दहू आंख कतहू कुछ नहीं। जब निजी कम्पनियों से राजनीतिक पार्टियों को फण्ड मिलता हो तो ये पार्टियां इन कम्पनियों के कुकर्मों पर पर्दा क्यों नहीं डालेंगी। कहावत है, ''जिसका खायेगा, उसका गायेगा।'' सवाल यह है कि क्या सरकार इस घोटाले की गम्भीता से जांच करवायेगी, क्योंकि घोटाले में अधिकांशत: कम्पनियां शामिल हैं, जिनके मालिकों पर केन्द्र सरकार की विशेष कृपा है। गौरतलब है कि संसद में पूछे गये इस घोटाले में सम्बन्धित सवाल का ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल ने अधूरा जवाब दिया और कम्पनियों तथा उनके मालिकों के नाम बताने पर चुप्पी साध ली। इसी से अन्दाज़ा लग जाता है कि जांच का नतीज़ा क्या होगा।

-ललित कुमार

राजमार्ग को लेकर छुटभैये कांग्रेसियों का 'विरोध प्रदर्शन'

छाज तो बोले छलनी भी क्या बोले जिसमें हजार छेद

फ़रीदाबाद (म.मो.) शहर के बीचों-बीच राजमार्ग पर निर्माण कार्यों के नाम पर चल रहे तमाशे के विरोध में कुछ छुटभैये कांग्रेसियों ने 5 अगस्त को प्रदर्शन किया। बाटा मोड़ स्थित निर्माणाधीन पुल के किनारे झंडे लेकर बैठे कांग्रेसियों ने निर्माण कार्यों में देरी के लिये भाजपा सरकार को दोषी ठहराते हुए नारेबाज़ी की तथा निर्माणकार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग की। धरना-प्रदर्शन से यातायात में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न पड़ने से पुलिस भी आराम से पेड़ों की छाया में खड़ी तमाशा देखती रही। लेकिन कड़ककड़ाती धूप में बैठे रहना कांग्रेसियों के लिये भारी पड़ रहा था, लिहाज़ा तुर्त-फुर्त फ़ोटो सैशन करा कर प्रदर्शनकारी अपने आप चलते बने।

इसमें कोई दो राय नहीं कि राजमार्ग को 6 लेन करने के नाम पर अनिल अम्बानी की कम्पनी रिलायंस इन्फ्रा ने 6 वर्ष से पूरे शहर को बंधक बना रखा है। जो काम 3 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिये था, वह अगले एक वर्ष तक भी पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिये मौजूदा भाजपा सरकार तो दोषी है ही लेकिन पूर्व की कांग्रेस सरकार भी कम दोषी नहीं है। उक्त दोनों पार्टियां अम्बानी परिवार के चन्दे पर पलती आई हैं।

विदित है कि सन् 2010 में कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने ही यह ठेका अम्बानी को दिया था। जबकि निर्माणकार्यों से अम्बानी का कोई वास्ता नहीं। सारा निर्माण कार्य देश की प्रतिष्ठित कम्पनी लार्सेन एंड टुब्रो (एल एन्ड टी) कर रही है। अम्बानी को तो यह ठेका केवल इस लिये दिया गया था ताकि वह इसके नाम पर दो टोल बूथों से (अब तीसरे की भी तैयारी है) जनता को लूट सके। इस लूट का भी एक नियम होता है जिसे कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। उस नियम के अनुसार काम पूरा होने के बाद ही टोल वसूला जाता है लेकिन इसके विपरीत अम्बानी को तुरन्त 2010 में ही लूट का लाइसेंस दे दिया गया। इसी लूट का एक चौथाई हिस्सा वह सड़क निर्माण कार्यों पर लगाता है, एक चौथाई राजनेताओं व अफ़सरों को भेंट चढ़ाता है तथा शेष अपनी कम्पनियों में लगाता है। गत वर्ष कैग (भारत के महालेखाकार) ने भी इस तथ्य की पुष्टि कर दी थी लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। करे भी कैसे, अम्बानियों का दिया जो खाते हैं।

निगमायुक्त आदित्य दहिया का तबादला होना ही था !

फ़रीदाबाद (म.मो.) डॉक्टर आदित्य दहिया जिस गति से नगर निगम के रिश्वतखोरों व हरामखोरों के गिरेबान तक पहुंचने जा रहे थे उसे देखने से ही प्रतीत होने लगा था कि वे यहां बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से वे हर फ़ाइल को सूंघ-सूंघ कर दस्तखत करते थे उससे न केवल भ्रष्ट अफ़सरों का दम घुटने लगा था बल्कि उनके राजनीतिक आका भी परेशान होने लगे थे। जिस तरह से वे खुद पैंट ऊंची करके बरसाती पानी में उतरकर भ्रष्ट एवं हरामखोर इन्जीनियरों को अपने साथ लगा कर जलभराव से निपटने लगे थे, यह भला खाये-पीये अघाये इन्जीनियरों को कैसे रास आ सकता था? अवैध निर्माणों एवं कब्ज़ों को लेकर जिस तरह वे अपने मातहतों की नकेल कसने लगे थे वह भला राजनेताओं को कैसे सुहा सकता था? लिहाजा गत सप्ताह उन्हें यहां से रुकसत करके करनाल के लिये रवाना कर दिया गया।

दरअसल राजनेता चाहते हैं कि डॉ. दहिया को संजीव चतुर्वेदी खेमका या कासनी जैसे अफ़सरों के पद चिन्हों पर चलने की बजाय खुल्लर जैसों से कुछ सीखना चाहिये जिससे न तो कोई राजनेता नाराज़ होगा और न ही तबादले, घर में लूट का माल आयेगा वह अलग से। डॉ. दहिया को यह भी समझना चाहिये था कि यदि सरकार वही सब चाहती जो वे कर रहे थे, तो निगमायुक्त की पोस्ट को महीनों-बरसों तक खाली ही क्यों रखती? विदित है कि डॉ. दहिया यहां एडीसी थे और निगम का चार्ज उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया गया था। यह प्रथा यहां लगातार चलती ही रहती है। जब कोई स्थाई आयुक्त यहां लगता भी है तो उसे केवल तब तक ही रखा जाता है जब तक वह यहां के तमाम घपले-घोटालों को न समझ पाये। समझने के बाद या तो वह उनमें अपनी हिस्सेदारी करले वरना चलने की तैयारी।

स्वत: सिद्ध है कि नगर निगम अफ़सरों द्वारा जो घपले-घोटाले हो रहे हैं वे सब सरकार की जानकारी एवं हिस्सेदारी में हो रहे हैं। टूटी सड़कें उफ़नते सीवर, सड़ते गंदगी के ढेर व गंदा पेयजल आदि सब कुछ सरकार द्वारा ही कराया जा रहा है। अब जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के धन की लूट-मार होने वाली है, उसके लिये जरूरी है यहां खुल्लर जैसों के ही चेले चांटे तैनात रहें।